

न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री महेन्द्र सोनी

आई.ए.एम

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1. उकाजी पुत्र पेलाजी पुरोहित
2. प्रताप पुत्र कपूराजी पुरोहित
3. डूंगाराम पुत्र सूरताराम जाति रेबारी
4. चुन्नीलाल पुत्र दीपाजी जाति सुधार
5. जबराराम पुत्र चमनाजी जाति
पुरोहित निवासीगण पावटी ग्राम
पंचायत डोरडा पंचायत समिति
जसवंतपुरा जिला जालोर

1. चतराराम उर्फ छगनलाल पुत्र दानाजी
जाति मेघवाल निवासी पावटी ग्राम
पंचायत डोरडा पंचायत समिति जसवंतपुरा
2. ग्राम पंचायत डोरडा ज रेंच, सरपंच
ग्राम पंचायत डोरडा पंचायत समिति
जसवंतपुरा जिला जालोर

प्रकरण पंचायत निगरानी संख्या

08/2018

रिविजन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत
ग्राम पंचायत डोरडा द्वारा दिनांक 10.06.1999 को स्वीकृत प्रस्ताव संख्या 3 पट्टा
दिनांक 15.09.1999 निरस्त (खारिज) करने बाबत

.....

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-

- 1-श्री नैनसिंह राजपुरोहित अभिभाषक प्रार्थीगण
- 2-श्री निखिल दवे अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
- 3.रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक:-08.01.2020

प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत डोरडा के प्रस्ताव संख्या 3
दिनांक 10.06.1999 ग्राम पंचायत डोरडा के विरुद्ध प्रस्तुत की है। उपरोक्त निगरानी
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद जांच के दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जांच
नोटिस के तलब किया गया। वांछित रेकार्ड भी तलब किया गया। अप्रार्थीगण की
ओर से दस्जावेज प्रस्तुत किये गये। संबंधित अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय
पक्ष की बहस सुनी गई।

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 चतराराम उर्फ छगनलाल ने ग्राम
पावटी में ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 10.06.1999 को प्रस्ताव संख्या 3 के
अनुसार अपने हक में रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बताया
गया तथा पट्टा दिनांक 15.09.1999 को अपने हक में जारी होना बताया तथा उस
पट्टे को लेकर हम प्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरुद्ध सलत हंग में राज्य सरकार की
भूमि खसरा नंबर 385 पर कब्जा करने की कोशिश की गई जो बिल्कुल ही गलत
है। अप्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। जो
पट्टा जारी किया जाना बताया है जो बिल्कुल ही फर्जी व कुटुरचित दस्तावेज है, जो
नियमानुसार जारी नहीं किये जाने से निम्न आधारों पर काबिल निरस्त है अप्रार्थी संख्या
1 ने दिनांक 10.06.1999 को ग्राम पंचायत डोरडा में राजस्थान पंचायत राज नियम
1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र
पेश किया। उसी दिन ग्राम पंचायत डोरडा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बिना कोई मंजूरी
किये बिना कोई पंचो की कमेटी से मौका रिपोर्ट मंगवाये बिना पट्टवारी अल्ला से भूमि
की किस्म के संबंध में बिना कोई जांच रिपोर्ट या राय लिखे 5/- रूपये वर्गमात्र के

हिसाब से पट्टा जारी करने का प्रस्ताव संख्या 3 स्वीकृत किया गया है, जो बिल्कुल ही गलत है। अप्रार्थी संख्या 2 को अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नये नियमानुसार दर्ज कर पत्रावली कायम कर तीन वार्ड पंचो की कमेटी नियुक्त कर उनसे मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक था तथा उसके बाद आवंटन किये जाने वाले भूखण्ड पर ग्राम पंचायत पर आपत्ति इस्तहार लगवाये जाकर डार रीतान प्राप्त करने थे। जिस आज्ञापक नियमों की पालना नहीं कर पट्टा जारी करने का प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 10.06.1999 को स्वीकृत कर दिनांक 15.09.1999 को पट्टा जारी किया गया है, जो पट्टा बिल्कुल ही गैर कानूनी व नियम विरुद्ध होने से काबिल खारिज है। उक्त प्रस्ताव में किस नाप तोल का पट्टा देने का प्रस्ताव पेश किया गया है। कहीं कोई उल्लेख नहीं है। जिससे प्रस्ताव काबिल खारिज है। पट्टा काबिल खारिज है। प्रार्थी द्वारा पट्टे में पडौस बताये जाकर सिविल न्यायाधीश भीनमाल के न्यायालय में जो दावा पेश किया है उस दावे में न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट भी मंगवाई गई है जिस मौका रिपोर्ट में मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा होना नहीं पाया गया है। पट्टा किस खसरा नंबर में जारी किया गया उसका भी कोई उल्लेख पंचायत के प्रस्ताव व पट्टे में नहीं है। जिससे पट्टा काबिल खारिज है। उक्त अप्रार्थी के पट्टे में निःशुल्क शब्द को काटकर अतिरिक्त ईबारत रियायती दर पर जोना गया है तथा विक्रय विलेख के पद संख्या 2 व 3 में कांट छोट की गई है जिस पर भी विक्रय विलेख जारी करने के प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है तथा उक्त पट्टे की पृष्ठ पर पडौस बाबत लिखी गई दिशाओं में तथा पडौस के नाम में कांट छोट की गई है। जिससे पट्टा काबिल खारिज है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जो विक्रय विलेख दिनांक 15.09.1999 को जारी किया गया है उस पर स्वयं आवंटनी अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर ही नहीं है। कानूनन सम्पत्ति अन्तर्गत अधिनियमों के प्रावधानों के तहत विक्रय विलेख निष्पादन के लिये दोनों पक्षकार विक्रेता व खरीदार के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। जब तक विक्रेता द्वारा निष्पादित दस्तावेज को वेदा स्वीकार नहीं करता तब तक ऐसा दस्तावेज शून्य है व कानूनन उसका कोई महत्व व मूल्य नहीं है जिससे उक्त विक्रय अपूर्ण होने से पट्टा काबिल खारिज है। अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी विक्रय विलेख (पट्टे) पर ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं है जो कानूनन आवश्यक है। विक्रय विलेख पर न तो पट्टा मंगवा अंकित है न ही कोई मिसल संख्या ही अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि पट्टा आवंटन हेतु न तो कोई मिसल कायम की गई और न ही नियमों की कोई पालना ही की गई तथा न ही पटवारी हल्का से या वार्ड पंचो से कोई रिपोर्ट ही मंगी गई इसके उल्लेख न तो पट्टे में है तथा न ही नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पालना नहीं की है, यहाँ तक कि भूखण्ड आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी का कहीं कोई अन्य मकान या प्लॉट पंचायत क्षेत्र में नहीं होने बाबत शपथ पत्र ही लिया है। आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं करने से दिनांक 10.06.1999 का प्रस्ताव संख्या 3 बिल्कुल ही गैर कानूनी व अवैध होने से काबिल खारिज है तथा उसके आधार पर दिनांक 15.09.1999 को जारी किया गया विक्रय विलेख (पट्टा) काबिल खारिज है। अप्रार्थी के पक्ष में जारी आबादी भूमि के विक्रय विलेख पट्टा के पद संख्या 8 में यह शर्त है कि इस भूमि पर आवंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान या झोंपड़ा इत्यादि बनाना अनिवार्य होगा। विक्रय विलेख दिनांक 15.09.1999 को जारी किया है जिस पर 13 वर्ष का लम्बा समय बितने के बावजूद न तो अप्रार्थी संख्या 1 का वहाँ पर कोई कब्जा रहा है और न कोई निर्माण किया है। पट्टे में बताई गई भूमि मौके पर बिल्कुल ही खाली पड़ी है जिसमें गाँवों के पानी पीने की पोकली चारा रखने का टर्मिनल बना हुआ है तथा भूमि गाँवों की आखरी के रूप में कदीम में काम आ रही है। अप्रार्थी द्वारा सिविल न्यायाधीश भीनमाल के न्यायालय में दावा पेश किया गिराने में पडौस पट्टे में बताये है उन पडौसियों की भूमि तो खसरा नंबर 335 रकबा 3.12 हेक्टर

की भूमि है जो भूमि राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज भूमि पंगड ग्रीवा तथा रास्ते की भूमि है जो गैर मुमकिन है भूमि पर गायो की आखरी है तथा राज्य सरकार की भूमि है जिस पर ग्राम पंचायत का कोई कानूनी हक नहीं है जहां पट्टा जारी करना बताया है वह भूमि खसरा नंबर 385 की भूमि है जो कभी भी ग्राम पंचायत डोरडा के खाते में न तो दर्ज रही न ही आबादी भूमि है। ग्राम पंचायत डोरडा अप्रार्थी संख्या 2 को राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज राजकीय भूमि का किसी भी व्यक्ति को आवंटित विक्रय करने का कतई अधिकार प्राप्त नहीं है, बिना अधिकार क्षेत्र के जारी किया गया पट्टा व प्रस्ताव काबिल निरस्त है। अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन के बाद कब कब्जा भौतिक रूप से सुपुर्द किया गया ग्राम पंचायत में कोई पट्टा कब्जा सुपुर्द नहीं है, न ही पट्टे में कोई कब्जा सुपुर्द करने का उल्लेख ही है। मौके पर भूमि बिल्कुल खाली है। कानूनी आवंटन के दो साल में निर्माण किया जाना आवश्यक था जो नहीं किये जाने से पट्टा काबिल निरस्त है। अप्रार्थी संख्या 1 सरकारी कर्मचारी है जो अध्यापक है, इस कारण उन्हें रियायती दर पर किया गया भूमि आवंटन काबिल निरस्त है। अप्रार्थी द्वारा सिविल न्यायाधीश भीनमाल के न्यायालय में पेश किये दीवानी विविध मुकदमा नंबर 37/2018 में न्यायालय द्वारा मौके कमिश्नर नियुक्त कर वादग्रस्त स्थल का मौका निरीक्षण दिनांक 03.08.2018 को किया गया है। जिस मौका रिपोर्ट की नकल साथ में पेश है। जिसमें विक्रय विलेख में बताई जा रही भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कोई कब्जा नहीं है वहां मौके पर श्री महादेव गौवर्धन गौधाम पवतो का लोहे का बोर्ड लगा है तथा एक छप्पर बना हुआ है तथा लोहे की एंगल लगाकर लोहे की चद्दरे लगाकर छप्परा बनाया हुआ है तथा गायो के पानी पीने के लिए पानी का होद बना हुआ है होद पर जय गाय माता की आखरी लिखा हुआ है तथा अन्दर गाये इधर उधर घुम रही है। मौके पर कहीं पर प्लाट के निशान नहीं है। मौके पर चारा पडा है। आवंटन की जाने वाली भूमि तथा पट्टे में बताई जाने वाली भूमि पर गायो की गौशाला व आखरी वर्तमान में स्थित है अप्रार्थी का कोई हक नहीं होने से पट्टा काबिल खारिज है तथा दिनांक 10.06.1999 को ग्राम पंचायत द्वारा लिया हुआ प्रस्ताव संख्या 3 काबिल खारिज है। अप्रार्थी संख्या 2 ने एक ही दिन दिनांक 10.06.1999 को आवंटन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थना पत्र लिया तथा उसी दिन बिना कोई मौका देखे व जांच किये प्रस्ताव संख्या 3 स्वीकृत कर रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसमें आवंटन किये जाने वाले प्लॉट का कोई नाप व तौल ही नहीं है इस कारण प्रस्ताव स्वीकृत करने की पूरी कार्यवाही व पट्टा जारी करने की पूरी कार्यवाही बिना आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये हुई है। जिससे काबिल खारिज है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कभी भी एक दिन भी कब्जा नहीं रहा इस कारण हमें उक्त पट्टे के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकी। अप्रार्थी ने अपनी अनुसूचित जाति का फायदा उठाकर सरकारी जमीन पर गलत कब्जा करने की नियत से सिविल न्यायालय में दावा किया व दिनांक 03.08.2018 को सिविल न्यायालय से मौका कमिश्नर मौका देखने आये तब कार्यवाही का पता लगा उसके बाद भीनमाल न्यायालय में जाकर वकील का पता लगाया तो फर्जी पट्टे बनने का पता लगा तब ग्राम पंचायत से गौशाला के कार्यकर्ता मुझ प्रार्थी जयगाम ने दिनांक 05.10.2018 को पट्टे की नकल व प्रस्ताव की नकल मांगी जो नकल दिनांक 15.10.2018 को पट्टे की नकल व प्रस्ताव की नकल मांगी जो नकल दिनांक 15.10.2018 व दिनांक 25.10.2018 को प्राप्त हुई नकले प्राप्त करने पर फर्जी रूप से विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी करने का ज्ञान हुआ जिस पर तुरन्त रिविजन प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं जो प्रस्ताव स्वीकृत करने व पट्टा जारी करने का पूर्णतया ज्ञान होने की जागेख में अन्दर न्याय पेश विविध विलेख आवंटन करने के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 10.06.1999 को हमारी रंग हाजरी में स्वीकृत हुआ व पट्टा दिनांक 15.09.1999 को जारी हुआ है जिसका हमें कतई

ज्ञान नहीं था वैसे भी उक्त प्रस्ताव व पट्टा बिल्कुल ही गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पर बिना कोई जांच किये जारी किया हुआ होने से एवजीसियों वोइड है जिसे निरस्त कराने हेतु म्याद कोई बाधा नहीं है। प्रार्थीगण ग्राम पावटी के मूल निवासी है तथा ग्राम पावटी के व श्री महादेव गौवर्धन गौधाम पावटी के प्रतिनिधि है इस कारण आम गांव के हित में प्रतिनिधि की हैसियत से उक्त रिविजन प्रार्थना पत्र जनहित में पेश है तथा हमे प्रार्थना पत्र पेश करने का कानूनी अधिकार क्षेत्र है।

अतः रिविजन प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 10.06.1999 के स्वीकृत किया गया पट्टा जारी करने का प्रस्ताव संख्या 3 निरस्त फरमाया जावे। तथा उक्त प्रस्ताव के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा बिलेख (पट्टा) दिनांक 15.09.1999 को निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रूप से दौराहते हुये कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 10.06.99 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र ग्राम पंचायत डारड में पेश किया गया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई रिपोर्ट, जांच करवाये बिना ही दिनांक 10.06.99 को उसी दिन पट्टा जारी करने का आदेश कर दिया गया। जो प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 10.06.99 से स्पष्ट है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सिविल कोर्ट भीनमाल में प्रार्थीगण के विरुद्ध एक दावा प्रस्तुत किया गया कि हमें पट्टे मिले हुये हैं जस पर कब्जा नहीं था पट्टा शुदा भूखण्ड पर करवाये जा रहे निर्माण कार्य को अप्रार्थीगण द्वारा बाधित किया जा रहा है, अतः अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवावे। इस दावे में भी स्पष्ट है कि पट्टा जारी वर्ष 1999 से लगाकर आज तक एकदिन आवंटन का विवादात्त भूखण्ड पर कब्जा अथवा निर्माण नहीं रहा है। सिविल कोर्ट भीनमाल द्वारा निर्दोष मौका कमिश्नर द्वारा दिनांक 03.08.2018 को विवादात्त भूखण्ड वादत मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसके अनुसार मौके पर भूखण्ड आवंटन का कोई कब्जा नहीं है। बल्कि भूखण्ड के चारो तरफ कांटो की वाड यनी हुई है। बीच में लोहे का बार्ड लगा हुआ है जिस पर श्री महादेव गौवर्धन गौधाम पावटी लिखा हुआ है। पस में लोहे की ऐगलो पर चददरो से बना हुआ छपरा है। उसी के पास मौके पर पावटी के पानी पीने का होज यानि अवाडा बना हुआ है। भूमि मौके पर खाली व खुली पड़ी है भूमि का उपयोग गायो की आखरीया के काम आने में मौके पर मवेशिया खड़ी पडती है। जहां गायो को चारा पानी दिया जाता है। विवादात्त भूमि ग्राम पावटी के खसरा नंबर 385 किस्म गैर मुमकिन सरकारी भूमि है जो पगडंडिया तथा रास्ते (चरणगाह के लिये नहीं) राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। इसके आधार पर यह भी स्पष्ट है कि विवादात्त भूखण्ड की भूमि गैर मुमकिन आबादी नहीं है। अप्रार्थी के नाम जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख (पट्टा) की शर्त संख्या 8 के अनुसार आवंटनी को दो वर्ष में अन्तर मकान या झोपडा इत्यादि बनाना अनिवार्य होता है जबकि आवंटनी द्वारा वर्ष 1999 से लगाकर आज तक इस भूखण्ड पर किसी प्रकार मकान अथवा झोपडा इत्यादि नहीं बनाया गया है। जिसके आधार पर भी पट्टा निरस्त योग्य है। पट्टे पर आवंटनी एवं ग्राम सेवक के हस्ताक्षरो का अभाव है जो आवश्यक होते हैं। आवंटनी को पट्टा किस्म खसरा नंबर की भूमि पर जारी किया गया, इसका उल्लेख ग्राम पंचायत के बैटक कार्यवाही रजिस्टर अथवा पट्टे पर नहीं है। तथा पट्टा जारी करने से पूर्व भूमि का किस्म आबादी है या नहीं इस बाबत भी पट्टागरे हल्का से रिपोर्ट नहीं ली गई है। आवेदक भूमिहीन है अथवा नहीं ऐसी भी ग्राम पंचायत द्वारा कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं ली गई है। विवादात्त भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं है सरकारी भूमि है जिस पर ग्राम पंचायत को पट्टा देने का अधिकार नहीं होने से पट्टा निरस्त योग्य

है। ग्राम पंचायत द्वारा एक ही दिन में पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया जो विधिसंगत नहीं है। अवैधानिक आदेश बाबत कोई लिमिटेशन लागू नहीं होती है। फिर भी प्रार्थीगण को पट्टे के संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही यह रिवीजन प्रार्थना पत्र समय सीमा में प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सर्वोच्च फरमाते हुये अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 10.06.1999 को पारित प्रस्ताव संख्या 3 को निरस्त फरमावे तथा उक्त प्रस्ताव के आधार पर अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया विक्रय विलेख (पट्टा) दिनांक 15.09.1999 को निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान तर्क दिया गया कि अप्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 10.06.1999 को प्रस्तुत किया गया जिस पर पंचायत द्वारा मौका जांच करने के आधार पर दिनांक 15.09.1999 को पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा एक ही दिन में कार्यवाही कर पट्टा जारी नहीं करती। तब भी अवधि बाद पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे की जानकारी प्रार्थीगण को वर्ष 2009 में होने पर उपखंड अधिकारी भीनमाल को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि अप्रार्थी बाड बनाकर अतिक्रमण कर रहे हैं। जिन्हें हटाने पर मुआयना जाति/जनजाति के मुकदमें में फसाने की धमकीयां दे रहे हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण को विवादित भूमि के संबंध में 2009 से जानकारी होने के बावजूद भी यह प्रार्थना पत्र वर्ष 2018 में प्रस्तुत किया गया है। जो म्याद बाहर है। तत्पश्चात् वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र वर्ष 2009 पावटी के गोलुआ गांव से संबंधित होना कथन किया गया। दिनांक 10.06.1999 को ग्राम पंचायत डोरडा द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव में चार व्यक्तियों को ही पट्टे नहीं दिये बल्कि अन्य व्यक्तियों को भी पट्टे जारी किये गये हैं। इसके आधार पर दिनांक 10.06.1999 को पारित किया गया प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। पट्टे पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं होना हमारा जिम्मेदारी नहीं है और पट्टे पर आवंटियों के हस्ताक्षर नहीं होना किसी प्रकार की अनियमिता भी नहीं है। सिविल कोर्ट भीनमाल द्वारा नियुक्त मौका कमिश्नर की रिपोर्ट में कमिश्नर द्वारा सभी चीजे नई प्रतीत होती है लिखा गया है। इससे यह साबित हो रहा है कि विवादित भूखण्ड पर पूर्व आवंटियों का कब्जा रहा है। इन सभी तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसूच्य प्रक्रिया अपनाई जाकर पट्टा जारी किया गया है तथा आवंटियों का मौका पर कब्जा भी रहा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिवीजन प्रार्थना पत्र सारहीन होने से सर्वोच्च फरमावे

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया एवं बहस के दिन्दुओं पर ध्यान भी किया। जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 10.06.1999 को रियायती दर पर भूखण्ड आवटन-आवेदन पत्र राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डोरडा में प्रस्तुत किया जाने पर दिनांक 10.06.1999 को बैठक कार्यवाही रजिस्टर के प्रस्ताव संख्या 3 में दर्ज कर यह इत्यरत लिख गये हैं कि उपरोक्त प्रार्थीगणों को प्लॉट रियायती दर पर देने हेतु पूर्व में मौका मुआयना कर दिया गया था जिसके आधार पर पंचायत अधिनियम 1996 के नियम 158 के तहत देने का निर्णय लिया गया, जिसमें ग्राम डोरडा व पावटी की आबादी सन् 1991 को उक्त संख्या के आधार पर 1000 से ज्यादा व 2000 से कम होने पर प्रति वर्ग गज 5/- रुपये के हिसाब से 750/- पंचायत कोष में जमा होने के पश्चात् प्रार्थीगणों को पट्टे जारी किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये। प्रस्ताव दिनांक 10.06.1999 के आधार पर दिनांक 15.09.1999 को अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी होने का कथन अप्रार्थी की ओर से किया गया है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.06.1999 को ही आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्व में मौका मुआयना करने का उल्लेख करते हुये पट्टा जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। ग्राम पंचायत द्वारा मौका मुआयना किससे द्वारा कब करवाया गया इसका विवरण प्रस्ताव संख्या 3 में नहीं है तथा न ही पूर्व में मौका मुआयना करने से संबंधित मौका रिपोर्ट ग्राम पंचायत से प्राप्त हुये रेकॉर्ड में उपलब्ध है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिवीजन प्रार्थना पत्र में विवादित

भूखण्ड को ग्राम पावटी के खसरा नंबर 385 में होना बताया गया है जो राजस्व अभिलेख जमाबंदी अनुसार किस्म गैर मुमकिन पगडडीयां तथा गस्ते(चारगाड के लिये नहीं) राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है। सिविल कोर्ट भीनमाल द्वारा नियुक्त मौका कमिश्नर की रिपोर्ट अनुसार विवादित भूखण्ड पर पट्टा धारक का कब्जा नहीं होकर गायो की आखरीया के उपयोग में लिया जा रहा है। जहां श्री महादेव गौधर्म गौधर्म पावटी लिखा हुआ लोहे का बोर्ड लगा हुआ है, लोहे की चददरो का हपरा बना हुआ है तथा पानी का एक होज बना हुआ है। इसी भूखण्ड पर अप्रार्थी द्वारा भूखण्ड के नाम पट्टा जारी होना तथा कब्जा होने का कथन किया है लेकिन अपने कथनों में उक्त भूखण्डो को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि होने के समर्थन में कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूखण्ड का आबादी भूमि नहीं मानते हुये सरकारी भूमि होना प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है। सरकारी भूमि का आबादी विस्तार हेतु जब तक ग्राम पंचायत को आवंटन नहीं हो जाता है तब तक सरकारी भूमि पर ग्राम पंचायत को विक्रय विलेख (पट्टा) जारी कराने की शक्ति प्राप्त नहीं है। साथ ही अप्रार्थी के नाम जारी पट्टे की शर्त संख्या 8 के अनुसार 2 वर्ष में मकान या झोपडा बनाना अनिवार्य होने के बावजूद भी आबादी अप्रार्थी द्वारा विवादित भूखण्ड पर किसी प्रकार का निर्माण सन् 1999 से आज तक नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा इस प्रकरण में विवादित भूखण्ड की आराजी को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि होने के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है तथा न ही विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी का पूर्व में कब्जा होना साबित हो रहा है।

उपरोक्तानुसार अप्रार्थी के नाम ग्राम पंचायत डोरडा द्वारा दिनांक 15.09.1999 को पट्टा जारी करने से पूर्व विवादित भूखण्ड की आराजी आबादी किस्म की है अथवा नहीं इस बाबत संबंधित पटवारी/तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं विवादित भूखण्ड में संबंधित मौका कमिश्नर द्वारा दिनांक 03.08.2018 को तैयार की गई मौका रिपोर्ट अनुसार पट्टा धारक अप्रार्थी का मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है तथा प्रार्थीगण विवादित भूखण्ड को ग्राम पावटी के खसरा नंबर 385 सरकारी भूमि में होना कथन कर रहे है इसके खण्डन में अप्रार्थी के पक्ष की ओर विवादित भूखण्ड को गैर मुमकिन आबादी भूमि में होना तथा उस पर पट्टा जारी होने की दिशा में 2 वर्ष के भीतर मकान अथवा झोपडा बनाया जाना साबित करने में असफल रहे है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 10.06.1999 को प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर नियमानुसार पट्टा जारी करने से पूर्व संबंधित पटवारी हल्का/तहसीलदार से भूमि की किस्म बचन रिपोर्ट प्राप्त कर विक्रय विलेख(पट्टा)जारी करने के लिये ग्राम पंचायत डोरडा स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत डोरडा द्वारा दिनांक 10.06.1999 को अप्रार्थी संख्या 2 चतराराम के नाम पट्टा जारी करने के प्रस्ताव संख्या 3 को निरस्त करते हुये विक्रय विलेख (पट्टा) दिनांक 15.09.1999 को निरस्त किया जाना है। पत्रावली संख्या 385 पर खसरा नंबर से कम हो।

Sd/-
(महेन्द्र सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
डोरडा

निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-
(महेन्द्र सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
डोरडा